24 साल बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) योजना में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब स्कूली बच्चे पहले नाश्ता करेंगे। इसके बाद पढ़ाई करेंगे। नाश्ते के एक घंटा बाद मध्याह्न भोजन दिया जाएगा।

जैसा नाम वैसा ही किया काम

हवलदार यश वीर सिंह तोमर

जन्म : 04 जनवरी, 1960 सिरसाली, उत्तर प्रदेश

शहीद हुए : 13 जून, 1999

यूनिट : 2 राजपूताना रायफल

शौर्य गाथा : कारगिल युद्ध के दौरान 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने का निर्देश मिला। ग्रेनेडियर्स के कई विफल प्रयासों के बाद राजपूताना रायफल की दूसरी बटालियन को हमले के लिए आगे किया गया। ग्रेनेडियर्स ने तीन प्वाइंट से राजपूताना को कवर दिया। मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में 90 सैनिक अंतिम हमले के लिए आगे बढ़े। इसी पलटन में यश वीर भी शामिल थे। यह पलटन प्वाइंट 4950 को अपने कब्जे में लेने के आखिरी चरण में

जरा याद करो कुर्बानी...

थी। 12 जून को पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी के बीच जब भारतीय सैनिक एक एक कर शहीद हो रहे थे, तो हवलदार यश वीर सिंह ने ग्रेनेड लेकर पाकिस्तानी बंकरों पर धावा बोला। उन्होंने बंकरों पर 18 ग्रेनेड फेंके और दुश्मनों को मार गिराया। उनके साहस को देखकर दुश्मनों के छक्के छूट गए। उनके पैर उखड़ने शुरू ही हुए थे कि इस दौरान वे गंभीर रूप से जख्मी हुए और शहीद हो गए। जब उनका शरीर मिला तो उसके एक हाथ में रायफल और दूसरे में ग्रेनेड थे। तोलोलिंग फतह करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

सपा-बसपा शासन की 23 सड़कों की होगी जांच

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- प्रयागराज और प्रतापगढ़ में बनीं इन सड़कों की तलाशी जा रही फाइलें
- सबसे ज्यादा यमुनापार में हुआ था सड़कों का निर्माण, ज्यादातर खराब

सड़कों का ब्योरा मांगा

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग हिमांशु मित्तल ने बताया कि वर्ष 2004 से लेकर 2012 तक प्रयागराज और प्रतापगढ़ में बनाई गई सड़कों का ब्योरा मांगा गया है। जल्द ही पूरी सूचना एसआइटी को दे दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा और मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार में मंडल के दो जिलों प्रयागराज व प्रतापगढ़ में बनाई गई 23 बड़ी सड़कों की जांच कराई जाएगी। यह जांच विशेष जांच प्रकोष्ठ (एसआइटी) करेगा। सड़क की गुणवत्ता से लेकर टेंडर और फर्म के बारे में छानबीन कराई जाएगी। फिलहाल प्रकोष्ठ की मांग पर फाइलें खंगाली जा रही है।

वैसे तो पूर्ववर्ती सरकारों में मंडल में दो सौ से ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुंदरीकरण और मरम्मतीकरण किया गया था। इसके अलावा स्टेट और नेशनल हाईवे भी बनवाए गए थे। शासन के निर्देश पर प्रयागराज की 17 और प्रतापगढ़ की छह सड़कें जांच के लिए चिह्नित की गई हैं। इनमें प्रयागराज के यमुनापार में मांडा रोड से भारतगंज-कोरांव, नारीबारी होते हुए लालापुर तक स्टेट हाईवे, सिरसा से कोरांव, रामपुर से कोहड़ार घाट, कोहड़ार घाट से कोरांव, मेजा रोड से खीरी, पचदेवरा से गौहनिया आदि सड़कें बनाई गईं थीं। इसी तरह गंगापार में झूंसी के चक से छिबैया, जमुनीपुर होते हुए हनुमानगंज, सैदाबाद से असढ़िया, हंडिया से फूलपुर, हंडिया से धनूपुर, फूलपुर से सोरांव, फाफामऊ से सहसों होते हुए हनुमानगंज की सड़कें बनी थीं। इन सड़कों से संबंधित फाइलें विशेष जांच प्रकोष्ठ (एसआइटी) ने मांगी है। अफसर फाइलें तलाश करा रहे हैं।

बताते हैं कि इन सड़कों के निर्माण में करोड़ों रुपये का घपला हुआ था। सड़कों के निर्माण में ज्यादा धनराशि खर्च करने से लेकर गुणवत्ता की भी शिकायतें आई थीं। इनमें कई ऐसी सड़कें हैं जो कुछ समय में ही क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनकी दोबारा मरम्मत कराई गई।

कर्नाटक में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं राज्यपाल

बेंगलुरु, आइएएनएस : कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला राज्य में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। जदएस-कांग्रेस गठबंधन के सभी बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिए जाने के कारण भाजपा फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश करने के मूड में नहीं है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता जी. मधुसूदन ने बताया, 'बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार या अस्वीकार करने में अगर स्पीकर ज्यादा समय लेते हैं तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करना चाहते।' उन्होंने आगे कहा, 'जब तक इस्तीफे स्वीकार नहीं हो जाते, विधानसभा की सदस्य संख्या 225 (मनोनीत समेत) बनी रहेगी और साधारण बहुमत का आंकड़ा 113 होगा। ऐसी स्थिति में दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बावजूद हमारे पास बहुमत से छह विधायक कम रहेंगे। अगर स्पीकर बागी विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं या उन्हें अयोग्य घोषित कर देते हैं तो विधानसभा की सदस्य संख्या घटकर 210 रह जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 106 होगा।'

इस बीच, राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वर्तमान राजनीतिक हालात में कोई भी स्थिर सरकार नहीं दे सकता। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्दरमैया ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्होंने ही बागी विधायकों को इस्तीफा देने के लिए उकसाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्दलीय विधायकों को याचिका वापस लेने की मंजूरी दी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों आर. शंकर और एच. नागेश को उनकी याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी। याचिकाओं में राज्य विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार को कुमारस्वामी सरकार द्वारा पेश विश्वास मत पर 'तत्काल' शक्ति परीक्षण कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पीकर और कार्यवाहक मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलों पर गौर किया कि उन्हें याचिका वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।

दो बागी कांग्रेस विधायक और एक निर्दलीय अयोग्य करार

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने गुरुवार को कांग्रेस के दो बागी विधायकों रमेश जर्किहोली व महेश कुमाताहल्ली और एक निर्दलीय विधायक आर. शंकर को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दे दिया। तीनों विधायक विधानसभा के शेष कार्यकाल यानी 2023 तक सदन की सदस्यता के अयोग्य रहेंगे। स्पीकर ने कहा कि वह शेष 14 मामलों में भी दो दिनों में फैसला ले लेंगे। स्पीकर ने कहा कि वह इस बात से आश्वस्त हैं कि उपरोक्त तीनों सदस्यों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए थे। उन्होंने बताया, 'उन्होंने संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसीलिए उन्हें अयोग्य ठहराया गया है।' आर. शंकर के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दरमैया ने उन्हें बताया था कि शंकर की पार्टी केपीजेपी का कांग्रेस में विलय हो गया था और उसके बाद ही उन्हें मंत्री बनाया गया था। लिहाजा वह कांग्रेस के निर्वाचित सदस्य थे।

मकोका पर भाजपा व कांग्रेस शासित राज्यों के दिखे अलग-अलग सुर

सख्त रुख ▶ नशे की समस्या पर अंतरराज्यीय कांफ्रेंस में सात राज्य राष्ट्रीय नीति बनाने पर सहमत

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश मकोका जैसे कानून के पक्ष में, पंजाब को कानून के दुरुपयोग की आशंका

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

नशे से निपटने के लिए चंडीगढ़ में आयोजित अंतरराज्यीय सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिभुवन सिंह रावत (बाएं से दाएं)। प्रेट्र

नशे की समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की तर्ज पर कानून बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुर गुरुवार को अलग-अलग रहे। भाजपा शासित हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इस तरह के कानून के हक में दिखे तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐसे कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चुप्पी साधे रखी।

नशे की समस्या पर पंजाब की मेजबानी में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई दूसरी अंतरराज्यीय कांफ्रेंस में सात राज्य राष्ट्रीय नीति बनाने पर सहमत हुए। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली व जम्मू-कश्मीर के अधिकारी नशे की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति पर पंजाब के साथ खड़े नजर आए। मकोका जैसे कानून पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हकोका और मकोका की तर्ज पर कानून संबंधी विचार कर रहा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने संगठित अपराध रोकने को हकोका (हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) बनाने के लिए सभी रास्ते साफ कर लिए हैं। 2 अगस्त को शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं, अलबत्ता राष्ट्रीय नीति का समर्थन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मकोका का विरोध नहीं किया, वे चुप रहे। उन्होंने जागरुकता पर विशेष जोर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मौजूदा कानून एनडीपीएस एक्ट को ही और मजबूत करने की बात की। उन्होंने मकोका जैसे कानून में सावधानी बरतने पर जोर देते हुए आशंका जताई कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग हो सकता है।

ठाकुर बोले-हिमाचल में नशा तस्करी करने वाले 40 फीसद पंजाबी : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नशा तस्करी करने वाले जितने भी युवा पकड़े जाते हैं उनमें 40 फीसद पंजाब से हैं, जबकि 26 फीसद हरियाणा के हैं। हिमाचल के युवा केवल दो फीसद हैं।

गहलोत ने कहा-राजस्थान में अफीम की खेती सरकारी नियंत्रण में : कैप्टन अमरिंदर ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से राज्य में अफीम की खेती पर पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सीमा से पंजाब में भारी मात्रा में अफीम की तस्करी हो रही है। इस पर गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अफीम की खेती सरकारी कंट्रोल में है और जितनी भी उपज होती है वह सारी सरकार खरीदती है। इसलिए वहां से तस्करी नहीं हो सकती।

अपनी कमजोर कड़ियों पर कांग्रेस की निगाह

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में बदले राजनीतिक हालात के बाद भाजपा की ओर से होने वाले संभावित पलटवार से कमलनाथ सरकार आशंकित है। यही वजह है कि वह सतर्क भी हो गई है। हार्स ट्रेडिंग से विधायकों को बचाने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की चेतावनी के बाद कांग्रेस ने अपनी कमजोर कड़ियों की निगरानी बढ़ा दी है। कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कांग्रेस और भाजपा में सियासी प्रबंधन के रणनीतिकार भोपाल से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हो गए हैं। विधायक दल की कमजोर कड़ियों को चिह्नित कर फोकस किया जा रहा है। निजी चर्चा में भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी और ब्यौहारी विधायक शरद कोल का असंतोष वह समझ नहीं पाए और धीरे-धीरे वह कांग्रेस के पाले में चले गए, लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों विधायकों द्वारा कमलनाथ सरकार को समर्थन देने का एलान करने से फिलहाल दलबदल जैसी कोई स्थिति नहीं है। उधर, पाला बदलने के बाद सरकार ने दोनों विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी है।

कांग्रेस का दावा-भाजपा के पांच विधायक और संपर्क में : कांग्रेस संगठन के दिग्गज नेता और मंत्रिगण गुरुवार को यह दावा करते रहे कि विधानसभा में मत विभाजन के जरिये हुआ फ्लोर टेस्ट (दो विधायकों की टूट) तो ट्रेलर मात्र है, अभी भाजपा के पांच अन्य विधायक भी उनके लगातार संपर्क में हैं। हालांकि, सतर्कता का माहौल कांग्रेस में भी है। निर्दलीयों के अलावा पार्टी के कुछ असंतुष्ट विधायकों पर नजर रखी जा रही है।

कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद ही मप्र में कांग्रेस सरकार को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई थी। भाजपा नेता कहते रहे हैं कि कर्नाटक से चली हवा अब मप्र तक पहुंचेगी। दो विधायकों के टूटने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भी एलान किया था कि खेल कांग्रेस ने शुरू किया खत्म हम करेंगे। कांग्रेस की घबराहट का कारण दरअसल नरोत्तम मिश्रा का यह बयान भी है। पार्टी नेता मान कर चल रहे हैं कि भाजपा चुप नहीं बैठेगी। कुछ न कुछ जरूर करेगी।

ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे कमलनाथ जिससे भाजपा नेतृत्व से टकराव दिखे

नईदुनिया, भोपाल

कमलनाथ फाइल फोटो

मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के दो विधायकों को अपने पाले में लाने के बावजूद मुख्यमंत्री कमलनाथ फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। वे अपने एक्शन, बयान और हाव-भाव से ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहते, जिससे भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से टकराव दिखाई दे। एक दिन पहले सदन में उन्होंने भाजपा के एक नंबर और दो नंबर को लेकर नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी पर बेहद संतुलित जवाब दिया और गुरुवार को ट्वीट के माध्यम से यह संदेश दिया कि इतना सब होने के बावजूद वे प्रदेश को दलगत राजनीति में नहीं बांटना चाहते।

कमलनाथ ने ट्वीट किया कि हम प्रदेश को विकास की दृष्टि से देश में शीर्ष पर ले जाना चाहते हैं। प्रदेश हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम प्रदेश को दलगत राजनीति में बांटना नहीं चाहते हैं। हम विपक्ष से भी शुरू से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में हमें सहयोग करे। हमें जनादेश मिला है। विपक्ष उसका सम्मान करे। हम अभी भी विपक्ष से प्रदेश हित में प्रदेश के विकास के लिए सहयोग की उम्मीद व अपेक्षा करते हैं। भाजपा इसे कमलनाथ का भय मानती है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल कहते हैं कि बुधवार का घटनाक्रम और गुरुवार का उनका ट्वीट यह बताता है कि वे कितनी घबराहट में हैं। उधर, प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनके मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा कहते हैं कि भाजपा के दो विधायकों को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए मुख्यमंत्री ने न तो प्रलोभन दिया और न ही कोई वादा किया। वे भाजपा में दुखी थे, इसलिए कांग्रेस के साथ हो लिए।

वहीं, भाजपा मप्र विधानसभा में हुए घटनाक्रम से बेहद नाराज है। बागी विधायकों के खिलाफ पार्टी अभी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, लेकिन परोक्ष रूप से उन्हें चेतावनी दे दी है कि वे बिना भाजपा के चुनाव जीतकर दिखा दें। कांग्रेस के संपर्क वाले दूसरे विधायकों को भी पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर भाजपा से दगा करने की गलती उन्होंने की तो मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें।

अब गाय के ऑक्सीजन छोड़ने के मुद्दे पर उत्तराखंड में सियासत

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट द्वारा नदी के पत्थर द्वारा आसान प्रसव को लेकर दिए गए बयान पर मचा घमासान अभी शांत भी नहीं हुआ है। वहीं, अब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान वायरल हो रहा है। इस बयान में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेने के साथ ही ऑक्सीजन छोड़ती भी है। इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि गाय के संपर्क में रहने से टीबी जैसे रोग दूर हो जाते हैं।

गुरुवार को सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री यह कहते दिख रहे हैं कि पीपल का पेड़ प्राणवायु छोड़ता है। ऐसे ही पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है तो ऑक्सीजन छोड़ता है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी को सांस की तकलीफ है तो गाय की मालिश करने से यह तकलीफ दूर हो जाती है। टीबी जैसी बीमारी भी गाय के संपर्क में आने से दूर हो जाती है। गाय के गोबर और गौमूत्र में काफी ताकत है। शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे स्किन, हार्ट और किडनी आदि के लिए ये काफी फायदेमंद हैं।

सोशल मीडिया में इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर तरह-तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालयों की मानें तो यह वीडियो तकरीबन पांच माह पुराना है और इसे जानबूझ कर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में जो कहा गया है वह प्रदेश में अभी तक चल रही मान्यताओं के आधार पर ही कहा गया है। इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में भी विपक्षी विधायक कांग्रेस के संपर्क में

नईदुनिया, रायपुर: मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने भाजपा खेमे में हलचल बढ़ा दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दावा किया है कि दो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जकांछ) के कई विधायक कांग्रेस के आला-नेताओं के लगातार संपर्क में हैं।

त्रिवेदी का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कामकाज से विपक्षी दलों के कई विधायक प्रभावित हैं। इस कारण वह कांग्रेस में आने की इच्छा जता रहे हैं। भाजपा और जकांछ के ऐसे विधायकों का स्वागत है, लेकिन उनके कांग्रेस में प्रवेश पर पार्टी नेतृत्व को फैसला लेना है। वैसे उन्होंने यह भी कहा कि 90 सदस्यीय विधानसभा में 68 विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए कांग्रेस सरकार को दूसरे दल के विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं है।

आप में बगावत, जयहिंद पर ब्राह्मणवाद फैलाने के आरोप, बागियों को पार्टी से निकाला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पंचकूला व सोनीपत के नेताओं ने खोला नवीन जयहिंद के खिलाफ मोर्चा, दबंगई के आरोप जड़े

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पंडित नवीन जयहिंद के खिलाफ कुछ पदाधिकारियों ने बगावत का झंडा उठा लिया। उन पर ब्राह्मणवाद फैलाने और दबंगई दिखाने के आरोप लगाए गए हैं। फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव जयहिंद ने अपने नाम के आगे पंडित शब्द लगाकर लड़ा था। जयहिंद का यह फैसला पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को नागवार गुजरा और उन्होंने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए।

आप के अंबाला लोकसभा सीट के प्रभारी व पंचकूला के अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा समेत कुछ पदाधिकारियों ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवीन जयहिंद की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इन पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी नाराजगी न तो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से है और न ही हरियाणा मामलों के प्रभारी गोपाल राय और सह प्रभारी सुशील गुप्ता से है, लेकिन नवीन जयहिंद को लेकर नाराजगी है।

उन्होंने कहा कि खुद की जाति हिंदुस्तान का नारा देने वाले नवीन जयहिंद ने लोकसभा चुनावों के दौरान पंडित नवीन जयहिंद लिखना शुरू कर जातिवाद को बढ़ावा दिया। यह सारी बातें पार्टी आलाकमान को पहुंचाई गई थीं, मगर हाईकमान ने कुछ नहीं किया। राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने निष्कर्ष निकाला कि समस्या केवल संवाद की कमी की है और नवीन जयहिंद के साथ मतभेद गंभीर प्रकृति में नहीं आते।

नवीन जयहिंद ने अपने विरुद्ध योगेश्वर शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी के प्रति बगावत व अनुशासनहीनता माना है। आप की हरियाणा इकाई के सह संगठन मंत्री अजय गौतम ने बताया कि अनुशासनहीनता के कारण पंचकूला के योगेश्वर शर्मा और सोनीपत के अनिल तुषीर को पार्टी से निकाल दिया गया है। दोनों ही पिछले कई माह से पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे थे। उन्हें कई बार चेतावनी दी गई, मगर उन्होंने अपनी आदत में सुधार नहीं किया। अजय गौतम के अनुसार अनिल तुषीर को पहले भी निष्कासित किया गया था, लेकिन व्यवहार में सुधार का भरोसा दिलाने पर उन्हें बहाल कर दिया गया था। अब फिर अनिल तुषीर और योगेश्वर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रति खुली बगावत की है, जिस कारण दोनों को निकाल दिया गया है।

डैमेज कंट्रोल की कवायद

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

ब्यौहारी विधायक शरद कोल और मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के पाला बदलने पर पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह को भोपाल भेजा। उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की पर उन्हें आंशिक सफलता भी नहीं मिली। इस दौरान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी प्रदेश कार्यालय में दिग्गजों के साथ सक्रिय रहे।

भाजपा में सब कुछ सामान्य होने का दावा : भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है। तनाव में कांग्रेस है और वह जबरिया अपनी ताकत दिखाने के लिए उल्टे-सीधे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा न तो पहले सरकार गिराने के पक्ष में थी और न उसका ऐसा कोई इरादा है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है।

दो टूक

शीर्ष अदालत में तुरंत सुनवाई के मुकदमों के सूचीबद्ध नहीं होने पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने नाराजगी जताई

कोर्ट की रजिस्ट्री में कुछ बुनियादी गड़बड़ी है : सीजेआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। तुरंत सुनवाई के मुकदमों के सूचीबद्ध नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए सीजेआइ ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष कोर्ट की रजिस्ट्री में 'बुनियादी रूप से कुछ गड़बड़ी है।'

मुख्य न्यायाधीश गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि रोजाना ऐसे वकीलों की लंबी कतार लगी होती है जो चाहते हैं कि उनका मामला सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे कार्यसूची से हटा दिया गया है। तीन अक्टूबर, 2018 को देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालने के दिन से न्यायमूर्ति गोगोई ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वकीलों को शीघ्र सुनवाई के लिए अपने मामले का उल्लेख नहीं करना पड़े और उनके मुकदमे एक निश्चित अवधि के भीतर अपने आप सूचीबद्ध हो जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'रोजाना मामले सूचीबद्ध कराने के लिए वकीलों की लंबी कतार लगी रहती है। निश्चित ही इसमें (रजिस्ट्री) कुछ बुनियादी गड़बड़ी है। सर्वश्रेष्ठ

रंजन गोगोई फाइल फोटो

प्रयासों के बावजूद, मैं इससे (मामले सूचीबद्ध कराने) निबटने में असमर्थ हूं।'

मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी उस समय की जब एक वकील ने अपने एक मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे कार्यसूची से निकाल दिया गया है। पीठ ने इसके बाद इस तथ्य का उल्लेख किया कि हाई कोर्ट में एक सप्ताह में करीब छह हजार नए मामले दायरे होते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस अवधि में करीब एक हजार मामले दायर होते हैं लेकिन इसके बाद भी शीर्ष कोर्ट की रजिस्ट्री प्रभावी तरीके से इनका निबटारा करने में असमर्थ है।

कोलेजियम नहीं, न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे चिंता का विषय : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली कोलेजियम की कार्यशैली नहीं बल्कि निचली अदालतों में बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों के पदों की रिक्तियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे न्यायपालिका के लिए चिंता का विषय है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने देश में बच्चों से दुष्कर्म मामलों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि से संबंधित मामले पर विचार के दौरान अपनी नाराजगी जताई और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी से दूर के स्थानों पर न्यायिक अधिकारियों को बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।

पीठ ने सवाल किया, 'त्रिपुरा, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वास्तविकता क्या है? मध्य प्रदेश जैसे राज्य अभी भी आरोपी और पीड़ित के बीच कोर्ट में एक पर्दा डालकर काम करने में यकीन करते हैं।' पीठ ने कहा, 'साकेत की अदालत में आपके पास गवाह के लिए कक्ष हो सकता है, लेकिन हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां ये सुविधाएं नहीं हैं। हमारे यहां ऐसे स्थान भी हैं जहां मजिस्ट्रेट चार फुट के कमरे में बैठते हैं। हमने यह देखा है और अदालतों की यही हकीकत है।' शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में न्यायिक अधिकारियों के पांच हजार से अधिक पद रिक्त हैं और विधायिका एक के बाद दूसरा नया कानून बना रही है। न्यायाधीश पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है और तमाम कानूनों में प्रावधान किया जाता है कि इससे संबंधित मामलों में छह महीने या एक साल के भीतर निर्णय हो।

पीठ ने कहा, 'कोई भी न्यायिक सुविधाओं और संरचनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो न्यायपालिका के लिए अधिक चिंताजनक हैं न कि कोलेजियम।'

भाजपा ने मिजोरम में बनाया क्रिश्चियन मिशनरी सेल

आइजल, आइएएनएस : ईसाई बहुल मिजोरम में कमल खिलाने की तैयारी के मद्देनजर पार्टी ने पहली बार राज्य में क्रिश्चियन मिशनरी सेल की स्थापना की है। बुधवार से इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई। राज्य की 40 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी का एकमात्र विधायक है। बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की कुल जनसंख्या 1,091,014 है। कुल आबादी के 87 फीसद लोग ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं।

भाजपा की मिजोरम इकाई के अध्यक्ष जेवी लूना ने कहा कि पांच सदस्यीय इस सेल का प्रमुख हरीथेरेंगा छांगटे को बनाया गया है जबकि जूली वनपारी को इसका सचिव बनाया गया है। छांगटे ने कहा कि सेल की स्थापना राजनीतिक दलों और चर्च के उस आरोप के खिलाफ की गई है, जिसमें वह भाजपा को ईसाई विरोधी बताते हैं। खनन इंजीनियर से राजनेता बने 54 वर्षीय छांगटे ने कहा कि शुरू में हम मिजो लोगों के बीच सामाजिक गतिविधियों की शुरुआत करेंगे और धीरे-धीरे इसका विस्तार करेंगे।

- ईसाई बहुल राज्य में कमल खिलाने की तैयारी में पार्टी

छांगटे ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि अध्ययन, नौकरी और चिकित्सा उपचार के लिए जब मिजो लोग अन्य राज्यों में जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है। यह सेल इस तरह की शिकायतों को दूर करने में मदद करेगा। सेल की 24 घंटे की एक हेल्पलाइन भी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नौकरी के दौरान मैंने गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, असम सहित देश के कई हिस्सों में काम किया है। कुल मिलाकर मेरा निष्कर्ष यह है कि भाजपा सबसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मिजोरम में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़े छांगटे ने कहा कि यह झूठ कांग्रेस ने फैलाया है कि भाजपा ईसाई विरोधी है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि पार्टी सत्ता में आए। बता दें कि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट भाजपा नीत नार्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस का एक घटक है, लेकिन दोनों पार्टियों ने विस और लोस चुनाव अलग-अलग लड़े थे।